International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal, **ISSN 2581-7795**

महिलाओं के समावेशी विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका

पंकज कुमार गुप्ता

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची
पीएच.डी. पंजीयन क्रमांक : 135729/20

डॉ० तमन्ना सिंह,

सहायक प्राध्यापिका,
मारवाड़ी कॉलेज,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत में समानता का युग प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त अवसर, समानता और न्याय की गारंटी प्रदान की गई लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के समावेशी विकास हेतु विभिन्न समय काल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सर्वांगिण विकास की रूपरेखा खिंचने का प्रयास किया गया। इसी के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजना का प्रारम्भ जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना के माध्यम से सामाजिक समावेशन के साथ–साथ आर्थिक समावेशन की भी बात की गई है। NRLM के अंतर्गत महिलाओं में सामाजिक पूंजी निर्माण की भावना का विकास हो रहा है साथ ही नेतृत्व क्षमता व निर्णय निर्माण और सामुदायिक भागीदारी में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल ने महिलाओं की आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्थिति में सुधार और लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। समावेशी विकास की इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे वे मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें।

मुख्य शब्द : वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन।

परिचय :

NRLM का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को उनके स्वयं के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत संसाधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है ताकि वे गरीबी से स्थायी रूप से बाहर आ सकें। मिशन की प्रमुख रणनीति है ''शक्ति प्रदान करना'' न कि ''सहायता करना'', जिससे समुदाय स्वयं निर्णय लेने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बन सके।

इस मिशन के तहत सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) में शामिल किया जाता है, जिन्हें सामूहिक बचत, आंतरिक ऋण, बैंक क्रेडिट लिंकेज, क्षमता विकास, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की सूविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावे, NRLM के अंतर्गत विभिन्न उप–घटक कार्यक्रम जैसे–महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP), स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) कृषि उद्यमी आदि शामिल है।

समावेशी शब्द का भारतीय परिपेक्ष्य में अर्थ यह है कि ''समाज के सभी लोगों का विकास बिना किसी वर्ग विशेष को छोड़े हुए'' राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समावेशी विकास में ग्रामीण महिलाओं चाहे वह किसी जाति, धर्म, या क्षेत्र के हों अगर उनमें काम करने की इच्छा है तो NRLM ऐसे गरीब पिछड़े, वंचित लोगों को सामुहिक रूप से सुविधा मुहैया कराने का काम विगत 14 वर्षों से कर रही है।

साहित्य समीक्षा :

- यूनुस मो. (2003) ''बैंकर टू द पुअर'' नामक पुस्तक में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने ग्रामीण बांग्लादेश में गरीब महिलाओं को छोटे कर्ज देकर ग्रामीण बैंक की नींव रखी। पारम्परिक बैंक जहाँ ऋण के बदले गारंटी की मांग करते हैं, वहीं यूनुस ने अपनी पुस्तक में इस धारणा को तोड़ने एवं एक सफल प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया।
- शर्मा, आर.के. (2021) ''राष्ट्रीय आजीविका मिशन : सशक्तिकरण की ओर'' नामक पुस्तक में लेखक ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की अवधारणा कार्यप्रणाली प्रभाव पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन रहा है। पुस्तक में मिशन के प्रमुख घटकों जैसे कि क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास, बैंक लिंकेज सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) और ग्राम संगठन पर विस्तृत चर्चा की गई है।

- वर्मा, संजीव (2019), ''ग्रामीण भारत में आजीविका मिशन की प्रभावशीलता'' नामक पुस्तक में लेखक NRLM की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में पुस्तक में विशेष रूप से बैंकिग सेवाएँ की महिला सदस्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है।
- चौहान, ममता (2020) ''महिला सशक्तिकरण और NRLM : एक सामाजिक अध्ययन'' नामक पुस्तक में महिला सशक्तिकरण और NRLM के अंतर्संबंधों को दर्शाती है। लेखिका ने महिला समूहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए बदलावों को रेखांकित किया है।

अध्ययन का उद्देश्य :

इस शोधपत्र के निम्न उद्देश्य रेखांकित है :–

क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन।

ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का मूल्यांकन।

विधितंत्र :

इस शोधपत्र के आँकड़ों का संग्रहण द्वितीयक स्रोतों के माध्मय से किया गया है। जिसमें मूख्य रूप से पत्र–पत्रिकाओं, NRLM की बेबसाइट का प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पंचसूत्र के माध्यम से महिलाओं में अनुशासन का विकास :

NRLM योजना में समूह संरचना के साथ ही पंचसूत्र का पालन करने सिखाया जाता है जिसमें नियमित बचत, नियमित बैठक, खाता बही का नियमित संधारण, नियमित अंतः ऋण व नियमित ऋण वापसी।[1]

पंचसूत्र एसएचजी के भीतर अनुशासन, आत्मविश्वास ओर वित्तीय प्रबंधन की भावना को सुदृढ़ कर रहा है। यह प्रत्येक समूह की नियमित्तता को देखने का सबसे सरल माध्यम है। इससे समूहों के वित्तीय अनुशासन की जानकारी प्राप्त होती है जिससे बैंक इन्हें ऋण देने या नहीं देने का निर्णय करते है।[2]

ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए परिक्रामी निधि व सामुदायिक निवेश निधि को व्यवस्था :

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लंबे समय से कमजोर रही है। विशेष रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की कमी ने इनके समग्र सशक्तिकरण को प्रभावित किया

है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जैसी योजनाओं के अंतर्गत परिक्रामी निधि तथा सामुदायिक निवेश निधि जैसी व्यवस्थायें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।[3]

परिक्रामी निधि की व्यवस्था :

परिक्रामी निधि का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता देना है ताकि वे अपने आंतरिक लेन–देन को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें और छोटे उद्यम प्रारम्भ कर सकें।

परिक्रामी निधि 10000 से 15000 की एकमुश्त सहायता होती है, जो एसएचजी की कार्यक्षमता, नियमित बैठकें बचत और आंतरिक लेनदेन के आधार पर दी जाती है।

परिक्रामी निधि के उपयोग से महिलाये आत्मनिर्भर बन रही हैं और छोटे–छोटे घरेलू उद्योग जैसे पशुपालन, दुकानदारी, सब्जी बिक्री आदि में लग रही है। इससे महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि हुई है और परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।[5]

सामुदायिक निवेश निधि (CIF) की व्यवस्था :

सामुदायिक निवेश निधि एक प्रकार की धूर्णनशील निधि है जो NRLM के अंतर्गत ग्राम संगठन अथवा संकुल स्तरीय संगठन को दी जाती है। इस निधि से सदस्यों की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी होती है।[6]

सामुदायिक निवेश निधि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम है। यह न सिर्फ अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया को भी मजबूत करता है।[7]

सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सशक्तिकरण व सामुदायिक शासन प्रणाली का विकास हो रह है जो कि महिलाओं के समावेशी विकास को दिखा रहा है।[8]

प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना :

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूहों को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए तैयार करती है जैसे :–

ड्रोन संचालन व मरम्मत का प्रशिक्षण :

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ''ड्रोन दीदी योजना'' एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन तकनीक प्रशिक्षित कर उन्हें कृषि सेवाओं में दक्ष बनाना है।

यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2024–25 के बजट में घोषित की गई थी और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।[9]

प्रत्येक चयनित महिला को ड्रोन संचालन, रख–रखाव और कृषि अनुप्रयोगों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सीविल एवियेशन द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है।[10]

जैविक कृषि संबंधित प्रशिक्षण :

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, और आज भी देश की दो–तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।[11]

जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई जैसे नवाचार, न केवल कृषि उत्पादन को टिकाऊ बनाते है, बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, झारखण्ड में जोहार योजना जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें बीज संरक्षण मल्चिंग, पोषण प्रबंधन, कीट नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं।[12]

निष्कर्ष :

महिलाओं के समावेशी विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्ती भूमिका है। ग्रामीण महिलायें आज समाज में आर्थिक व सामाजिक क्रांती ला रही है साथ ही भारतीय सामाजिक ताना–बाना में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं एवं नित नये बुलंदियों को छू रही हैं।

संदर्भ सूची :

1. कुमार. ए. (2021), वूमन इम्पावरमेन्ट थ्रू एनआरएलएम : ए केस स्टडी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुम्स इन झारखण्ड, जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट स्ट्डीज, पेज–12–25
2. सिंह, पी. एण्ड शर्मा, एम. (2020), सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एण्ड फाइनेंसियल इंक्लूजन इन रूरल इण्डिया : इम्पैक्ट ऑफ पंचसूत्र, रूरल इकोनॉमी एण्ड लाइवलीहूड रिव्यू
3. कुमार.ए. (2019), वूमन इम्पावरमेन्ट थ्रू एसएचजी अंडर एनआरएलएम : ए केस स्टडी ऑफ बिहार, जरनल ऑफ सोशल एण्ड इकोनॉमिक स्ट्डीज, 65–73
4. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट (2013), फ्रेमवर्क फोर इप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहूड मिशन, गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
5. वर्ल्ड बैंक (2020), इम्पावरिंग वूमन थ्रू एनआरएलएम : अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनीशिएटिव इन इण्डिया
6. वर्ल्ड बैंक (2015), प्रोजेक्ट अप्रेजल डॉक्यूमेन्ट्स फोर नेशनल रूरल लाईवलीहूड प्रोजेक्ट, रिपोर्ट नम्बर : 64412

7. जीविका बिहार रूरल लाईवलीहूड प्रमोशन सोसाईटी (2022), एनुअल रिपोर्ट 2021–22
8. सिन्हा, एफ, एण्ड मार्टिन, आई. (2021), फाइनेंसियल इन्क्लूजन थ्रू कम्यूनिटी इन्क्लूजन इन इण्डिया : द केस ऑफ सीआईएफ
9. प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (फरवरी, 2024), यूनियन बजट 2024–25 हाइलाइट्स : ड्रोन दीदी टू इम्पावर वूमन फार्मर, गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
10. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एवियेशन (2023), सिविल एवियेशन, रिक्वायरमेन्ट्स फोर ड्रोन ऑपरेशन, गवमेंन्ट ऑफ इण्डिया
11. प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो, (2021 जुलाई 24), टू–थर्ड ऑफ इण्ड्याज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर : पीआईबी रिपोर्ट
12. जीविका बिहार (2023), एनुअल रिपोर्ट : लाईवलीहूड थ्रू एग्रो–इकोलॉजी एण्ड वाटर, एफिशिऐंसी।